THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (e) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Development of land allotted to group housing societies

*1*832. SHRI SURAJ PRASAD:

SHRI M. BASAVARAJU:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that DDA gave possession of land to group housing societies in March, 1983 and assured them that the land would be developed within six months of the date of possession;

(b) whether it is also a fact that the land has not yet been developed;

(c) if so, what are the reasons therefor; and

(d) by when the land is likely to be developed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHD. USMAN ARIF): (a) The DDA gave possession of land to 66 cooperative group housing societies in March 1983. No commitment about completion of the development within six months thereof was made.

(b) to (d) Large-scale development of land takes time requiring coordination between the DDA, MCD, DESU and other concerned agencies. The planning and development work of the sites are in different stages of progress. In some locations the development work is held up due to court stay orders. However the societies can start construction work on their sites after obtaining the clearance of the building plans.

उत्तर प्रदेश में गांवों के लिए पेय-जल

833. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां 1983–84 के वर्ष के दौरान पेय जल की सप्लाई की गई है ;

(ख) ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां पेय-जल की सप्लाई अभी की जानी है ; और

(ग) ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां 1984–85 के वर्ष के दौरान पेय जल की सप्लाई किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1983–84 के दौरान, 8000 समस्याग्रस्त ग्रामों के लक्ष्य की तुलना में, 11,554 समस्याग्रस्त ग्रामों को (7704 ग्रामों को आंशिक रूप से और 3850 ग्रामों को पूर्ण रूप से) स्वच्छ पेय जल सुविधाओं से लाभान्वित किया गया है ।

(ख) तथा (ग) 1–4–1980 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पता लगाए गए 28,505 ग्रामों में से, 31 मार्च, 1984 तक 18,955 ग्रामों को लाभान्वित कर दिया गया है और 9,550 ग्राम शेष रह गए हैं । आशा है शेष ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् 31 मार्च, 1985 तक लाभान्वित कर दिया जाएगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि

834. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983–84 के वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है;

(ख) उन किसानों को अदा की गई प्रतिपूर्ति की दर कितनी है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ;

(ग) ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी प्रतिपूर्ति अदा की जानी है और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार इन किसानों के पुनर्वास के सम्बंध में विचार कर रही हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग, निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल

835. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूदों को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूदों को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार, विभिन्न राज्यों को कितना-कितना धन आवंटित किया गया ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार के पास ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं की योजना है, जिसमें, खेल कार्यकलापों में ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे युवकों को बड़ी संख्या में सम्मिलित करने का लक्ष्य है । योजना के अंतर्गत, तालुका/जिला/राज्य स्तर पर राज्य सरकारों/राज्य खेल परिषदों द्वारा प्रतियोगितायें आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं ।

केन्द्रीय सरकार राज्य खेल परिषदों को अनुदान देने की योजना भी चला रही है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना/अनुरक्षण के लिए बराबरी के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्य-वार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है ।

Deployment of Central Industrial Security Force at Paradip Port

83C. SHRI GAYA CHAND BHUYAN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the port-wise break up of employees in each of the major ports as on 31st March, 1984;

(b) what is the break up of number of Central Industrial Security Force deployed in each port;

(c) what are the reasons for deployment of more Central Industrial Security Force in Paradip Port, through the number of employees there is much less than other big ports like Bombay and Calcutta and the volume of transactions there is also much less; and

(d) what is the expenditure borne by Paradip Port for maintaining Central Industrial Security Force for the years 1981—84?